

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)

भारतसरकार

\*\*\*\*\*

‘हरकामदेशकेनाम’

नई दिल्ली: श्रावण 17, 1944

सोमवार: 08 अगस्त 2022

निर्मित और निर्माणाधीन सीमावर्ती सड़कों की स्थिति

भारतीय सेना द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकता के अनुसार किसी क्षेत्र की रणनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता है। विगत पांच वर्षों के दौरान सीमा पर निर्मित सड़कों का वर्ष-वार व्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्मित सड़कें (कि.मी. में)
2017-18	612.82
2018-19	608.62
2019-20	691.22
2020-21	940.64
2021-22	741.70
<b>कुल</b>	<b>3595.00</b>

इसके अतिरिक्त, 6195 कि.मी. की सीमा सड़कें निर्माणाधीन है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के आसान आवागमन हेतु परिवहन सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त, ये सड़कें आपातकालीन मामलों में सैन्य टुकड़ियों के त्वरित जुटान में भी लाभदायक हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न सिर्फ दूरवर्ती गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं अपितु क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सहायता करती हैं।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजराज्यसभामेंश्री  
जावडेकरद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयहजानकारीराज्यसभाकेपटलपररखी।

प्रकाश

एसआर/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)

भारतसरकार

\*\*\*\*\*

‘हरकामदेशकेनाम’

नई दिल्ली: श्रावण 17, 1944

सोमवार: 08 अगस्त 2022

"रक्षाउत्कृष्टताकेलिएनवाचार (आईडेक्स) " पहल

सरकारद्वारासूक्ष्म, लघुएवंमध्यमउद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स, निजीप्रवर्तकों, अनुसंधानएवंविकाससंस्थानोंतथाअकादमियोंसहितउद्योगोंकोशामिलकरतेहुएरक्षाऔरएरोस्पेससेक्टरमेंनवाचार औरप्रौद्योगिकीविकासकोप्रोत्साहितकरनेएवंआत्मनिर्भरताकोबढ़ावादेनेकेलिएरक्षाउत्कृष्टताहेतुनवाचार (आईडीईएक्स) फ्रेमवर्कशुरूकियाथा।सरकारनेवर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षोंकेलिए 498.78 करोड़रु. कीबजटीयसहायताकेसाथआईडीईएक्सकेलिएएककेन्द्रीयक्षेत्रकीयोजनाअनुमोदितकीहै।इसयोजनाकाउद्देश्यतकरीबन 300 स्टार्ट-अप/एमएसएमई/निजीप्रवर्तकोंऔरलगभग 20 पार्टनरइन्क्यूबेटरकोरक्षानवाचारसंगठन (डीआईओ) केमाध्यमसेवित्तीयसहयोगप्रदानकरनाहै।

सरकारस्टार्ट-अपकोपर्याप्तअनुदान, विभिन्नसरकारीएजेंसियोंकेपासउपलब्धपरीक्षणसुविधाओं/अवसंरचनातकसरलऔरतेजपहुँच, सुगमसंचालनात्मकप्रक्रियाओंऔरन्यूनतमदस्तावेजीकरणकाप्रयोगकरकेसह-सृजनऔरसह-नवाचारप्रदानकरकेतथाअधिप्राप्तिकोसुविधाजनकबनाकरसंपूर्णकार्यव्यवस्थाकोउनकेलिएसहायकबनातेहुएउन्हेंरक्षाक्षेत्रमेंसहयोगकरनेऔरदेशमेंएरोस्पेससेटअपविकसितकरनेकेलिएप्रोत्साहितकरतीहै।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजराज्यसभामेंडाकिरोडी लाल मीणाद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयहजानकारीराज्यसभाकेपटलपररखी।

एसआर/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)

भारतसरकार

\*\*\*\*\*

‘हरकामदेशकेनाम’

नई दिल्ली: श्रावण 17, 1944

सोमवार: 08 अगस्त 2022

रक्षाबलोंकापुनर्गठनकियाजाना

सुरक्षाचुनौतियोंकेसमग्रपरिदृश्यकोपूराकरनेकेलिएसशस्त्रबलोंकोतैयाररखनेहेतुजोखिमअवधारणा, संक्रियात्मकचुनौतियोंऔरप्रौद्योगिकचुनौतियोंकेआधारपररक्षाबलोंकाआधुनिकीकरण/ सुधारएकसततप्रक्रियाहै।

हथियारनिर्भरताकोकमकरनेऔररक्षाउपस्करकेस्वदेशीविनिर्माणकोप्रोत्साहितकरनेकेलिएसरकारीवित्त पोषणऔरउद्योगवित्तपोषणदोनोंकेसाथनिजीभागीदारीद्वारारक्षाउपस्करकेस्वदेशीडिजाइनऔरविकासकोसुगमब नानेहेतुडीएपी-20 मेंएकव्यापकसंशोधित ‘बनाओऔरनवाचार’ प्रक्रियाकीशुरुआतकीगईहै।

सकारात्मकस्वदेशीकरणसूचियों

(पीआईएलएस)

कीप्रगामीघोषणारक्षाहथियारोंऔरउपस्करोंजिन्हेंविदेशसेआयातितनहींकियाजाएगाकीसकारात्मकस्वदेशीकरणसू चियोंकीएकश्रेणीकीघोषणाकीगईहै।पहलीसकारात्मकस्वदेशीकरणसूचीजिसमें 101 मदेंशामिलहैं, कीघोषणाअगस्त, 2020 मेंकीगईथी, दूसरीसकारात्मकस्वदेशीकरणसूचीजिसमें 108 मदेंशामिलहैं, कीघोषणामई, 2021 मेंकीगईएवंतीसरीस्वदेशीकरणसूचीजिसमें 101 मदेंशामिलहैंकीघोषणाअप्रैल 2022 मेंकीगई।

रक्षाविनिर्माणमें ‘आत्मनिर्भरभारत’ काप्रभावनिम्नानुसारहै:

(i) वित्तवर्ष 2022-23 केलिएबजटघोषणाकेअनुरूपरक्षाअनुसंधानऔरविकासकेलिएआबंटित 25% उद्योगप्रेरितअनुसंधानऔरविकासकेलिएमेक I, मेक II, एसपीवीमॉडलऔरआईडीईएक्सरूटोंकेअंतर्गतउद्योगप्रेरितडिजाइनऔरविकासकेलिएसरकारद्वारा 18 मुख्यप्लेटफॉर्मोंकोअनुमोदनदियागयाहै।

(ii) एमएसएमई, स्टार्टअप्स, निजीनवोन्मेषकों, अनुसंधानऔरविकाससंस्थानोंतथाशैक्षिकसंस्थानोंसहितउद्योगोंकोशामिलकरकेरक्षाऔरएरोस्पेसमेंनवाचारऔर प्रौद्योगिकीविकासकोआगेबढानेतथाभारतीयरक्षाऔरएरोस्पेसआवश्यकताओंकेलिएभविष्यमेंअपनाएजानेकीसंभा वनावालेअनुसंधानऔरविकासकरनेमेंउन्हेंअनुदान/ वित्तपोषणएवंअन्यसहायताउपलब्धकरानेकेलिएअप्रैल

2018

में रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार

(आईडीईएक्स)

नाम से रक्षा के लिए एक नवाचार पारिप्रणाली शुरू की गई है। अब तक 125 समस्याएं प्रकट की गई हैं, 136 स्टार्टअप को शामिल किया गया है, 102 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii)

खरीद के आईडीईएक्स रूट का सरलीकरण किया गया है और परीक्षण प्रक्रिया में सुधार करके समय सीमा जो पहले 2 वर्ष थी, को घटाकर मात्र 5 माह कर दिया गया है।

(iv)

सरकार ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ाने और स्टार्टअप को सहायता देने के लिए 498.78 करोड़ रु. (2021-22 से 2025-26) के परिचय वाली एक स्कीम अनुमोदित की है। इससे 300 से अधिक स्टार्टअप नई डिजाइन और विकास परियोजनाओं में भागीदार बनने तथा 20 सहभागी इनक्यूबेटरों को सहायता देने में भी समर्थ होंगे।

(v)

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और डीपीएसयू द्वारा निर्यात को न्यूनतम करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में विभाग द्वारा सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की गई है। इस सूची में 2500 आयातित मदें शामिल हैं जिनका स्वदेशीकरण पहले ही किया जा चुका है और 351 उच्च मूल्य आयातित मदें जिनका स्वदेशीकरण अगले 3 वर्षों में किया जाएगा, शामिल हैं। 351 मदों में से 147 मदों का स्वदेशीकरण पहले ही किया जा चुका है।

(vi)

107 लाइन रिप्लेसेबल यूनिटों (एलआरयू) / उच्च मूल्य प्लेटफॉर्म की उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण हेतु डीपीएसयू की एक अन्य सूची दिनांक 28.03.2022 को अधिसूचित की गई थी। अब तक 4 एलआरयू का स्वदेशीकरण किया जा चुका है; 5 एलआरयू परीक्षण चरण में हैं और 31 एलआरयू डिजाइन और विकास चरण में हैं।

(vii)

आयात प्रतिस्थापन के लिए एमएसएमई/स्टार्टअप/ उद्योग विकास सहयोग प्रदान करने हेतु उद्योग इंटरफेस के साथ डीपीएसयू/ ओएफबी/सेवाओं के लिए अगस्त 2020 में सृजन नामक स्वदेशीकरण पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक, पहले आयात की गई 21000 से अधिक रक्षा मदों को इस पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। 388 निजी विक्रेताओं ने 4700 से अधिक मदों के स्वदेशीकरण में रुचि व्यक्त की है और अब तक 410 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

(viii)

स्वदेशी विकास और रक्षा उपकरण के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 'मेक-II' श्रेणी (उद्योग द्वारा वित्तपोषित) के लिए एक अलग प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। इस प्रक्रिया में योग्यता मानदंडों में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्तिगत रूप से दिए गए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रावधान आदि जैसे कई उद्योग हितैषी प्रावधान शामिल किए गए हैं। अभी तक थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना से संबंधित 72 परियोजनाओं को 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान किया गया है। सेनाओं द्वारा 38 आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन), 05 विकसित प्रोटोटाइपों और 02 अधिप्राप्ति संविदाओं पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ix)

इसके अलावा, परीक्षण प्रक्रिया का सुधार करके अधिप्राप्ति के मेक-II रूट को सरल कर दिया गया है और समय सीमा जो पहले 2 वर्ष थी, को घटाकर मात्र 5 महीने तक कर दिया गया है।

(x)

व्यापारकेसुगमीकरणकेभागकेरूपमें, निर्यातप्रक्रियाकोसरलऔरपूरीतरहसेऑनलाइनकरदियागयाहै।इसकेपरिणामस्वरूपजारीकिएगएनिर्यातप्राधिकारपत्रोंकीसंख्याबहुतबढ़गईहै।

(xi) रक्षापरीक्षणअवसंरचनायोजना (डीटीआईएस) बनाईगईहैताकिदेशमें 6 से 8 ग्रीनफील्डरक्षापरीक्षणअवसंरचनाओंकेनिर्माणहोसकेऔरघरेलूउद्योगहेतुरक्षापरीक्षणअवसंरचनामें "आत्मनिर्भरता" लाईजासके।

(xii) आजादीकाअमृतमहोत्सवकेभागकेरूपमें, सरकारने 11 जुलाई, 2022 को 'एआईडीईएफ' कार्यक्रमकाआयोजनकियाजिसमेंपहलीबारमाननीयरक्षामंत्रीद्वारा 75 रक्षाविशेषआर्टिफिशियलइंटेलिजेन्स (एआई) उत्पादलॉन्चकिएगएथे।कार्यक्रमकेदौरान, सार्वजनिकक्षेत्रकेरक्षाउपक्रम (डीपीएसयू) केतीनएआईउत्पादभीबाजारकेलिएलॉन्चकिएगएथे।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजराज्यसभामेंश्रीसंदोषकुमारपीद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयह जानकारीराज्यसभाकेपटलपररखी।

**एसआर/डीके/डीएस**

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)

भारतसरकार

\*\*\*\*\*

‘हरकामदेशकेनाम’

नई दिल्ली: श्रावण 17, 1944

सोमवार: 08 अगस्त 2022

रक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स

सरकार द्वारा सूक्ष्म (एमएसएमई) उद्यमों मध्यम एवं लघु, स्टार्टअप्स निजी, प्रवर्तकों, रक्षा हुए करते शामिल को उद्योगों सहित अकादमियों तथा संस्थानों विकास एवं अनुसंधान और एरोस्पेस सेक्टर में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार फ्रेमवर्क (आईडीईएक्स) शुरू किया गया था। अभी तक आईडीईएक्स फ्रेमवर्क के अन्तर्गत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 7 के (डीआईएससी) संस्करण शुरू हो चुके हैं। अनेक स्टार्टअप्स ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के विभिन्न चक्रों में भाग लिया है।

आईडीईएक्समार्गकेअन्तर्गत,  
सरकारनवाचारऔरअभिकल्पनएवंविकासपरबलदेतीहैतथासफलप्रोटोटाइपविकासकेलिएस्टार्टअप्सऔरप्रवर्तकों कीसहायताकरतीहै।अभीतक 136 स्टार्टअप्सकोशामिलकियागयाहैऔरप्रोटोटाइपविकासकेलिए 102 संविदाओंपरहस्ताक्षरकिएगएहैं।इसकेअलावा,  
मंत्रालयनेआईडीईएक्सविजेताओंकोआर्डरभेजनेकेलिएमार्गप्रशस्तकरतेहुए 14  
आईडीईएक्सउत्पादोंकेलिएआवश्यकताहेतुस्वीकृति (एओएन) भीप्रदानकीहै।

सरकारनेवर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षोंकेलिए 498.78 करोड़रु. कीबजटीयसहायताकेसाथआईडीईएक्सकेलिएकेंद्रीयक्षेत्रकीएकयोजनाअनुमोदितकीहै।

रक्षासेनाओंकीओरसेप्रकटहोनेवालेप्रोब्लमस्टेटमेंट्सप्रौद्योगिकीऔरप्रोटोटाइपकेविकासहेतुआईडीईएक्स फ्रेमवर्ककेअंतर्गतलांचकिएजातेहैं, जिससेरक्षासेनाओंकीवास्तविकसमयकीसमस्याएंदूरहोजातीहैं।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजराज्यसभामेंश्री  
पीद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयहजानकारीराज्यसभाकेपटलपररखी।

संदोष

कुमार

एसआर/डीके/डीएस